सम्पादकीय

प्रिय मित्रों

आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। देश के समक्ष उत्पन्न समस्त राजनीतिक आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का वास्तविक समाधान ढूँढने की बजाए इन समस्याओं पर राजनीतिक बयान बाजी ज्यादा हो रही है। अभी हाल के संसदीय सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे कई अहम् बिल आनन फानन में पारित किए गए ताकि उसका लाभ चुनावों में सत्ताधारी दल ले सके तथा अपने को जनता का वास्तविक हमदर्द बता सके। उधर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर सत्ता परिवर्तन की आस में चुनावी जंग तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर जिले में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगो पर भी राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही है। आगामी चुनाव में हर दल अपने फायदे नुकसान की दृष्टि से आए दिन संवेदनशील क्षेत्रों में दौरा कर एक दूसरे को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है।

दरअसल यह राजनीतिक परिदृश्य कई सवाल खड़ा करता है। क्या देश की समस्याओं का समाधान सिर्फ चुनावी रणनीति में ही ढूँढा जाना श्रेयस्कर है। मंहगाई, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सड़के, बिजली, पानी, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी समस्यायें जिनका सम्बन्ध आम आदमी के दैनिक जीवन से है उनके लिए राजनीतिक दलों के पास आम सहमति एवं ठोस समाधान का क्या पूर्णतया अभाव है। दैनिक जीवन में उपभोग की वस्तुएं निरन्तर मंहगी होती जा रही है। पैट्रोल–डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियाँ एवं फल आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से लोग बेघर हो रहे हैं। दंगो के कारण वर्षों से मातृत्व भाव में सरोबार लोग गाँवों से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी दशा में राजनीतिक दलों द्वारा सिर्फ चुनावी रण–भेरी बजाना तथा आरोपों प्रत्यारोपों के बीच भावी भारत का स्वप्नलोकीय चित्र उपस्थित करना देश के सुधि नागरिकों को रास नहीं आ रही है।

विडम्बना यह है कि चाहे वह मुद्रा के निरन्तर अवमूल्यन का सवाल हो, मंहगाई पर काबू पाना हो, अथवा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो सत्तासीन राजनीतिक दल के पास न तो कोई ठोस योजना है न ही दृढ़ राजनीति सद्इच्छा। जिसका परिणाम यह है कि हमारा देश निरन्तर असफल राज्यों की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी आन्तरिक दुर्व्यव्यवस्था का ही परिणाम है कि पाकिस्तान एवं चीन की घुसपैठ हमारी सीमाओं में निरन्तर बढ़ रही है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालद्वीप, छोटे पडोसी देश भी हमारी तुलना में चीन से सामीप्य चाहते हैं। गृहनीति, विदेशनीति, अर्थनीति एवं कूटनीति आज ठोस उपायों एवं सुदृढ़ रणनीति की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारें दूरगामी नीतियों एवं परिणामों एवं विकल्पों पर गहन विचार करनें के बजाए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में उलझी हुयी हैं।

प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से, चुनावी दाव–पेंच से, देश के सामने जो चुनौतियाँ है उनका समाधान हो जाएगा। यह सत्य है कि वर्तमान केन्द्रिय सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुयी हे लेकिन आगामी चुनाव के बाद यदि सत्ता परिवर्तन होता है तब भी क्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक समस्याओं का कोई समाधान हो पाएगा इसको

लेकर आम जनमानस में एक बेचैनी है। चुनावी गणित के सभी पहुलाओं पर विचार करने पर एक स्थायी पूर्ण बहुमत वाली सरकार की अपेक्षा करना जनता के लिए कठिन है क्योंकि राजनीतिक दलों की आन्तरिक स्थिति भी बहुत स्वस्थ नही है। तीसरे मोर्चे की उम्मीद लगाए समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास भी कोई ठोस विकल्प नही है। एक विषम राजनीतिक परिस्थिति में देश की जनता अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढ रही है। अतः राजनीतिक दलों को गम्भीर आम्मंथन कर देश की समस्याओं पर वास्तविक ध्यान केन्द्रित करना होगा अन्यथा हमारे गणतंत्र की साख वोट बैंक की राजनीति की बलिवेदी पर बलिदान होती नजर आएगी।

दिनांक : 15 अगस्त 2013

(मधुरेन्द्र कुमार)